

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4810/2010

मेसर्स राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-प्रबंधक (एफ एंड ए) श्री आर.के. सिंह. के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण, स्कोप मीनार, कोर-II, चौथी मंजिल, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092-रजिस्ट्रार के माध्यम से।
2. सहायक भविष्य निधि आयुक्त, जयपुर, निधि भवन, ज्योति नगर, जयपुर।

----प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री प्रान्जुल चोपड़ा, श्री समीर शर्मा एवं श्री कार्तिक गोयल के साथ
प्रत्यर्था (गण) की ओर से	:	श्री दीपक गोयल

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

आदेश

रिपोर्टेबल

आदेश सुरक्षित करने की तिथि : 24.01.2023

आदेश उच्चारित करने की तिथि : 29.03.2023

1. वर्तमान याचिका पीठासीन अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एटीए 509(12) 2006 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2010 के विरुद्ध जिसका शीर्षक राजस्थान सरकार खान और खनिज लिमिटेड बनाम सहायक भविष्य निधि है और आयुक्त जयपुर एवं कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952की धारा 14 ख के तहत सहायक भविष्य निधि आयुक्त जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2006 के विरुद्ध दायर की गई है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 19.02.2010

और 04.08.2006 के आदेश कानून की स्थापित स्थिति का उल्लंघन करते हुए पारित किए गए हैं और उक्त आदेश पारित करते समय, अपीलार्थियोंओं ने प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं किया है। मामले में न ही उन्होंने क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना लगाने और ब्याज पर संबंधित शुल्क से संबंधित *जस एड रेम* वैधानिक प्रावधानों के आदेश का पालन किया है। इसलिए, आक्षेपित आदेश गैर-स्थायी और प्रारंभ से ही अवैध है।

3. इस पृष्ठभूमि में, यहां ऊपर उल्लिखित आदेशों को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को वर्तमान याचिका के संक्षिप्त और प्रासंगिक तथ्यात्मक मैट्रिक्स से अवगत कराया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता राजस्थान सरकार का एक उद्यम है, जो रॉक फॉस्फेट, लिग्नाइट, जिप्सम, सिलिका और चूना पत्थर के खनन कार्य करता है। याचिकाकर्ता कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (इसके बाद, '1952 का अधिनियम') और कर्मचारी पेंशन योजना 1971 के शासनादेश के अंतर्गत आता है। हालाँकि, 1952 के अधिनियम के प्रावधान याचिकाकर्ता पर केवल इस सीमा तक लागू थे कि याचिकाकर्ता 1952 के अधिनियम की धारा 17(1)(क) के तहत एक छूट प्राप्त प्रतिष्ठान है। याचिकाकर्ता-कंपनी, लाभ के संकल्प के साथ इसके कर्मचारियों ने 'आरएसएमडीसी लिमिटेड कर्मचारी पेंशन विनियम, 1994' शीर्षक से 1.04.1994 से 1971 की कर्मचारी पेंशन योजना के बदले में एक पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा। याचिकाकर्ता-कंपनी के निदेशक मंडल ने 1994 के उक्त विनियमों को 1994 से लागू करने का संकल्प लिया। इस बीच, उस अवधि के दौरान जब 1994 के उक्त विनियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा था, केंद्र सरकार, अर्थात् ईपीएफ विभाग ने 'कर्मचारी पेंशन योजना, 1995' शुरू की।

4. इस समय, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता-कंपनी के 1994 के विनियमों का कार्यान्वयन 1.4.2014 से किया जाना था। 01.04.1994 को, याचिकाकर्ता-कंपनी ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई 1995 की पेंशन योजना से छूट देने के अनुपालन और तौर-तरीकों के संबंध में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के साथ बातचीत की। इसके बाद, 1995 की योजना के तहत याचिकाकर्ता-कंपनी के कर्मचारियों के प्रतिरोध और अशांति के तथ्य को ध्यान में रखते हुए और 1994 के विनियमों के संभावित कार्यान्वयन के तथ्य पर विचार करने के बाद, गठित समिति द्वारा जांच के अधीन निदेशक मंडल;

[2023/RJJP/001668]

याचिकाकर्ता-कंपनी ने 1995 की योजना के पैराग्राफ 39 का लाभ उठाने का निर्णय लिया, जो प्रतिष्ठानों को 1995 की पेंशन योजना के संचालन से छूट प्रदान करता है। इसलिए, पैराग्राफ 39 में परिकल्पित लाभ पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता-कंपनी ने पेंशन निधि में ऐसा योगदान नहीं किया।

5. इसके बाद, चूंकि 1994 के पेंशन विनियमों को अंतिम रूप देने में देरी हो रही थी, जो 01.04.1994 से प्रभावी होने थे; दिनांक 23.12.1996 को पत्र के माध्यम से, यह पी.एफ. द्वारा सुझाया गया था। अधिकारियों का कहना है कि पेंशन अंशदान की राशि याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा पेंशन फंड में भेजी जाएगी और उसे 1995 की पेंशन योजना के पैराग्राफ 39 के तहत छूट के अधीन वापस कर दिया जाएगा। उक्त सुझाव के आलोक में, याचिकाकर्ता-कंपनी ने 23.12.1996 को बकाया राशि जमा कर दी। इसके अलावा, 1994 के विनियमों को अंतिम रूप दिए जाने पर, याचिकाकर्ता-कंपनी ने 1995 की योजना के पैराग्राफ 39 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें 1994 के विनियमों के बदले में 1995 की पेंशन योजना से छूट दी गई थी, जैसा कि द्वारा तैयार किया गया था। याचिकाकर्ता-कंपनी हालाँकि, पत्र दिनांक 11.04.1997 के माध्यम से, उक्त छूट आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि 1994 के विनियमों को 1995 की पेंशन योजना के साथ तुलना करने पर कर्मचारियों के लिए कम अनुकूल माना गया था। इसके बाद, 19.02.2003 को, पूर्ववर्ती आरएसएमडीसी को याचिकाकर्ता-कंपनी में मिला दिया गया। इसके बाद, 28.10.2004 को, प्रबंध निदेशक (आरएसएमडीसी) के नाम पर 1952 के अधिनियम की धारा 14 ख के तहत समन जारी किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया था कि आरएसएमडीसी अंशदान शुल्क, निर्धारित नियत तारीख में पीएफ की राशि भेजने में विफल रहा था। उक्त सम्मन के आलोक में याचिकाकर्ता-कंपनी से आवश्यक विवरण/स्पष्टीकरण मांगा गया था। 17.01.2005 को, याचिकाकर्ता-कंपनी के एक प्रतिनिधि ने कंपनी के विरुद्ध की गई जांच में भाग लिया और दिनांक 15.01.2005 के पत्र के माध्यम से अपीलार्थियोंओं को कंपनियों के एकीकरण के तथ्य से अवगत कराया और प्रस्तुत किया कि पूर्ववर्ती आरएसएमडीसी 20.02.2003 से नियमित रूप से अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन कर रहा था और तदनुसार, अपना बकाया जमा कर रहा था।

6. इस पृष्ठभूमि में, 06.06.2006 को, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 18.05.2006 को

[2023/RJJP/001668]

एक पत्र जारी किया, जिसमें मार्च 1995 से लेकर मार्च 1995 तक की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 14 ख के तहत याचिकाकर्ता-कंपनी की ओर से देय राशि दर्शाने वाला एक विवरण भी शामिल जिसके साथ मार्च 1995 से अगस्त 2002 की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 14 ख के तहत याचिकाकर्ता-कंपनी की ओर से देय राशि को दर्शाने वाला एक विवरण भी शामिल है, जिसे धारा 14 ख के तहत नुकसान के रूप में 6,09,117 रुपये और अधिनियम की धारा 7 थ के तहत ब्याज @ 21,768 रुपये निर्धारित किया गया था। उत्तर में, याचिकाकर्ता-कंपनी ने पत्र दिनांक 13.07.2006 के माध्यम से अपना उत्तर प्रस्तुत किया, इस तथ्य के आलोक में अपनी प्रामाणिकता और वास्तविकता को आगे बढ़ाते हुए कि दिसंबर 1995 से फरवरी 1997 के बीच की अवधि के लिए नुकसान याचिकाकर्ता-कंपनी पर लागू नहीं होगा। तथ्य यह है कि विलंब, जैसा कि अपीलार्थियों द्वारा बताया गया है, इस तथ्य के कारण हुआ कि 1994 के पेंशन विनियमों को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और पैराग्राफ 39 के तहत दायर आवेदन खारिज कर दिया गया था। इसलिए, अपरिहार्य परिस्थितियों में अनजाने में देरी हुई। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता-कंपनी के इरादे नेक थे, जैसा कि इस तथ्य से पता चलता है कि जब 1994 के पेंशन विनियमों को अंतिम रूप देने में उनकी ओर से देरी हुई, तो याचिकाकर्ता-कंपनी ने वर्ष 1996 में वैधानिक योगदान अपनी मर्जी से जमा करना शुरू कर दिया। इसलिए, नीचे के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता-कंपनी के वास्तविक इरादों पर विचार किए बिना और मामले के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को नजरअंदाज किए बिना, विधिक रूप से अस्थिर आदेश पारित कर दिया है। अतः दिनांक 19.02.2010 और 04.08.2006 के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

7. इसके विपरीत, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उचित सोच-विचार करने और प्रासंगिक तथ्यों और लागू कानून पर विचार करने के बाद, लागू आदेश कानून के अनुसार पारित किए गए हैं। उन्होंने **सिविल अपील संख्या 2136/2012 शीर्षक हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन गोनिकोप्पल, कूर्ग बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन** में माननीय उच्चतम न्यायालय के 1952 के अधिनियम की धारा 14ख के तहत क्षतिपूर्ति निर्णय पर भरोसा किया है जिसमें यह माना गया था कि अधिनियम के तहत नियोक्ता द्वारा ईपीएफ योगदान के भुगतान में कोई भी डिफॉल्ट या देरी शुल्क लगाने के

लिए एक अनिवार्य शर्त है। इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि **हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट (सुप्रा.) बनाम धर्मेन्द्र टेक्सटाइल प्रोसेसर्स और अन्य। (2008) 13 एससीसी 369** में प्रकाशित में माननीय उच्चतम न्यायालय ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय पर विचार किया है और माना गया है कि नागरिक दायित्वों और देनदारियों में जुर्माना/क्षतिपूर्ति लगाने के लिए आपराधिक मनःस्थिति एक आवश्यक तत्व नहीं है। अंत में, अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के नियम 32 ख पर भरोसा किया, जिसे यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

32ख. नुकसान में कमी या छूट के लिए नियम और शर्तें:-

केंद्रीय बोर्ड निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन, धारा 14ख के दूसरे प्रावधान में निर्दिष्ट किसी प्रतिष्ठान के संबंध में अधिनियम की धारा 14ख के तहत लगाए गए नुकसान को कम या माफ कर सकता है, अर्थात्:-

(क) श्रमिकों की सहकारी समिति को उपक्रम के हस्तांतरण सहित प्रबंधन में बदलाव के मामले में और किसी अन्य औद्योगिक कंपनी के साथ रुग्ण औद्योगिक कंपनी के विलय या समामेलन के मामले में, नुकसान की पूरी छूट की अनुमति दी जा सकती है;

(ख) ऐसे मामलों में जहां औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, अपनी योजनाओं में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इस संबंध में सिफारिश करता है, 100 प्रतिशत तक नुकसान की छूट की अनुमति दी जा सकती है;

(ग) अन्य मामलों में, योग्यता के आधार पर, नुकसान में 50 प्रतिशत तक की कमी की अनुमति दी जा सकती है।

8. इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियम 32 ख के संदर्भ में, याचिकाकर्ता-कंपनी उप-नियम (ग) के वैधानिक दायरे में आती है। इसलिए, उक्त नियम के आदेश के अनुसार, यह केवल केंद्रीय बोर्ड है, जो किसी मामले की योग्यता के आधार पर, धारा 14 ख के तहत लगाए गए नुकसान को केवल 50% की ऊपरी सीमा तक कम या माफ कर सकता है। इसलिए, मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स और संबंधित कानून के आवेदन पर विधिवत विचार करने के बाद, अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ-साथ सहायक भविष्य निधि आयुक्त ने कानून के अनुसार सख्ती से तर्कसंगत आदेश पारित किए हैं। अतः वर्तमान रिट याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

9. इस न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों को सुना है, मामले के रिकॉर्ड को देखा है और बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया है।

10. मौजूदा मामले में, मामले के निष्पक्ष और प्रभावी निर्णय के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर गहन विचार की आवश्यकता है:

10/1. यह कि याचिकाकर्ता-कंपनी है और सरकारी-कंपनी होने के नाते इसके पास सरकार की 100 प्रतिशत इक्विटी है।

10/2. याचिकाकर्ता-कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए 'आरएसएमडीसी लिमिटेड कर्मचारी पेंशन विनियम, 1994' शीर्षक से एक पेंशन योजना शुरू की। हालाँकि, जब उक्त विनियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा था, केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 पेश की। तदनुसार, याचिकाकर्ता-कंपनी ने 1995 की योजना के पैराग्राफ 39 के तहत छूट के लिए आवेदन किया, जो 16.11.1995 से चालू हो गई।

10/3. चूंकि 1994 के पेंशन विनियमों को अंतिम रूप देने में देरी हो रही थी, जो 01.04.1994 से प्रभावी होने वाले थे, इसलिए पी.एफ. अधिकारियों द्वारा यह सुझाव दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि पेंशन योगदान की राशि याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा पेंशन फंड में भेजी जाएगी और उसे 1995 की योजना से छूट के अनुदान पर वापस कर दिया जाएगा। तदनुसार, देय राशि 23.12.1996 को इस विश्वास के तहत जमा की गई थी कि यदि छूट दी गई तो राशि वापस कर दी जाएगी।

10/4. हालाँकि, 1995 की योजना के पैराग्राफ 39 के तहत दायर छूट के लिए उक्त आवेदन 11.04.1997 को खारिज कर दिया गया था।

11. उपरोक्त तथ्यों पर गौर करने पर, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता-कंपनी नियमित रूप से 1952 के अधिनियम के प्रावधानों और उस पर लागू योजनाओं का अनुपालन कर रही थी और पेंशन योजना के लिए समय पर अपना वैधानिक योगदान भी जमा कर रही थी। इसके अलावा, उन्होंने 1952 के अधिनियम की धारा 14 ख के तहत याचिकाकर्ता-कंपनी के विरुद्ध जांच शुरू करने पर विभाग के साथ सहयोग भी किया। याचिकाकर्ता-कंपनी की विश्वसनीयता इस तथ्य से भी स्थापित होती है कि जब इसमें देरी हुई थी 1994 के पेंशन विनियमों को अंतिम रूप देने के बाद, याचिकाकर्ता-कंपनी ने अपनी मर्जी से, इस वास्तविक विश्वास के तहत अपना वैधानिक योगदान जमा करना शुरू कर दिया कि यदि पैराग्राफ 39 के तहत प्रार्थना की गई छूट दी जाती है, तो राशि कंपनी को वापस कर दी जाएगी। इसलिए, उपरोक्त पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता-कंपनी की प्रामाणिकता

स्थापित करने के बाद, विचार का केंद्रीय बिंदु जो तत्काल मामले में उठता है वह है-

“क्या 1952 के अधिनियम की धारा 14ख के प्रावधानों के आलोक में, हर्जाना लगाना अनिवार्य है या नहीं और क्या यह याचिकाकर्ता-कंपनी की ओर से अपने वैधानिक दायित्वों से बचने के लिए आपराधिक इरादे की आवश्यकता को समाहित करता है” भविष्य निधि या पेंशन योजना इस तरह के अधिरोपण/क्षतिपूर्ति के लिए पूर्व-आवश्यकता है?

12. यहां ऊपर दिए गए मुद्दे के निर्णय पर विचार करने से पहले, इस न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह इसके उचित विचार के लिए आवश्यक प्रासंगिक प्रावधानों को यहां प्रस्तुत करे:

“14ख. हर्जाना वसूलने की शक्ति- जहां कोई नियोक्ता फंड [(पेंशन) फंड या बीमा फंड] में किसी भी योगदान के भुगतान में या उप-धारा (2) के तहत उसके द्वारा स्थानांतरित किए जाने वाले आवश्यक संचय के हस्तांतरण में चूक करता है। धारा 15 [या धारा 17 की उपधारा (5)] या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या [किसी योजना या बीमा योजना] के तहत देय किसी भी शुल्क के भुगतान में या धारा 17 के तहत निर्दिष्ट शर्तों में से किसी के तहत, [केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है] "नियोक्ता से दंड के माध्यम से ऐसे नुकसान की वसूली कर सकता है, जो कि बकाया राशि जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है: से अधिक नहीं होगी।”

[बशर्ते कि ऐसी क्षतिपूर्ति लगाने और वसूलने से पहले, नियोक्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा]:

[परंतु यह भी कि केंद्रीय बोर्ड किसी ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में इस धारा के तहत लगाए गए नुकसान को कम या माफ कर सकता है जो एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी है और जिसके संबंध में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा पुनर्वास के लिए एक योजना को मंजूरी दी गई है। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 4, ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, जो योजना में निर्दिष्ट की जा सकती हैं।]

32ख. नुकसान में कमी या छूट के लिए नियम और शर्तें:-

केंद्रीय बोर्ड निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन, धारा 14ख के दूसरे प्रावधान में निर्दिष्ट किसी प्रतिष्ठान के संबंध में अधिनियम की धारा 14ख के तहत लगाए गए नुकसान को "कम या माफ" कर सकता है, अर्थात्:-

(क) श्रमिकों की सहकारी समिति को उपक्रम के हस्तांतरण सहित प्रबंधन में बदलाव के मामले में और किसी अन्य औद्योगिक कंपनी के साथ

रुग्ण औद्योगिक कंपनी के विलय या समामेलन के मामले में, नुकसान की पूरी छूट की अनुमति दी जा सकती है;

(ख) ऐसे मामलों में जहां औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, अपनी योजनाओं में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इस संबंध में सिफारिश करता है, 100 प्रतिशत तक नुकसान की छूट की अनुमति दी जा सकती है;

(ग) अन्य मामलों में, योग्यता के आधार पर, नुकसान में 50 प्रतिशत तक की कमी की अनुमति दी जा सकती है।

13. यहां ऊपर दिए गए केंद्रीय मुद्दे को निपटाने के लिए, **हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट(सुप्रा.) धर्मेन्द्र टेक्सटाइल्स (सुप्रा.)** के मामले में निर्णय, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय को पढ़ना जरूरी है, जिसमें उच्चतम न्यायालय पर भी भरोसा किया गया है। उक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थियों/ओं द्वारा यह काफी तर्क दिया गया है कि नागरिक दायित्वों और देनदारियों के उल्लंघन के लिए जुर्माना या हर्जाना लगाने के लिए *मेन्स री* या *एक्टस रीस* आवश्यक तत्व नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता ने, विशेष रूप से, उक्त निर्णय के निम्नलिखित उद्धरण पर भरोसा जताया, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"15. यह देखा जा सकता है कि **दिलीप एन. श्रॉफ (सुप्रा.)** जिस पर भरोसा किया गया था, उसे **भारत संघ और अन्य बनाम धर्मेन्द्र टेक्सटाइल प्रोसेसर्स और अन्य (सुप्रा.)** मामले में इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। उपरोक्त कारणों से, **कर्मचारी सरकार बीमा निगम (सुप्रा.)** में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार इस विषय पर बाध्यकारी मिसाल नहीं हो सकता है और अपीलार्थियों को कोई सहायता नहीं मिल सकती है।

17. **भारत संघ और अन्य बनाम वी. धर्मेन्द्र टेक्सटाइल प्रोसेसर्स और अन्य (सुप्रा.)**, में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, जो वास्तव में हमारे लिए बाध्यकारी है, हमारा मानना है कि अधिनियम के तहत नियोक्ता द्वारा ईपीएफ योगदान के भुगतान में कोई भी चूक या देरी, धारा 14ख के तहत हर्जाना लगाने के लिए अनिवार्य है। अधिनियम 1952 और *मेन्स री* या *एक्टस रीस* नागरिक दायित्वों/देनदारियों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/क्षतिपूर्ति लगाने के लिए एक आवश्यक तत्व नहीं है।"

14. दूसरी ओर, अपने वैधानिक दायित्व से बचने के लिए किसी प्रतिष्ठान की ओर से आपराधिक मनःस्थिति की आवश्यकता को स्थापित करने के लिए, जिससे 1952 के अधिनियम की धारा 14 ख के तहत जुर्माना लगाया जा सके, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा मैसर्स में उच्चतम न्यायालय के प्रसिद्ध निर्णय **हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम**

उड़ीसा सरकार की रिपोर्ट 1970 एससीआर (1) 753 पर व्यापक रूप से भरोसा किया है, विशेष रूप से, उक्त निर्णय से उक्त उद्धरण पर जोर दिया गया है, जिसे यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

7. अधिनियम के तहत डीलर के रूप में पंजीकरण न कराने पर जुर्माना लगाया जा सकता है: अधिनियम की धारा 9(1) धारा 25(1)(क) के साथ पठित। लेकिन जुर्माने का भुगतान करने का दायित्व केवल डीलर के रूप में पंजीकरण में चूक के प्रमाण पर उत्पन्न नहीं होता है।
वैधानिक दायित्व को पूरा करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाने का आदेश एक अर्ध-आपराधिक कार्यवाही का परिणाम है, और जुर्माना आमतौर पर तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि पार्टी या तो जानबूझकर कानून की अवहेलना करने के लिए बाध्य न हो या अपमानजनक या बेईमान आचरण का दोषी न हो, या अपने दायित्व की जानबूझकर उपेक्षा करते हुए कार्य किया। जुर्माना भी सिर्फ इसलिए नहीं लगाया जाएगा कि ऐसा करना वैध है। वैधानिक दायित्व को पूरा करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए या नहीं, यह न्यायिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले प्राधिकारी के विवेक और सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करने का मामला है। भले ही न्यूनतम जुर्माना निर्धारित किया गया हो, जुर्माना लगाने में सक्षम प्राधिकारी को जुर्माना लगाने से इनकार करना उचित होगा, जब अधिनियम के प्रावधानों का कोई तकनीकी या अनैतिक उल्लंघन होता है या जहां उल्लंघन एक वास्तविक विश्वास से होता है कि अपराधी कानून द्वारा निर्धारित तरीके से कार्य करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। कंपनी के मामलों के प्रभारी लोगों ने कंपनी को एक डीलर के रूप में पंजीकृत करने में असफल होने पर ईमानदार और वास्तविक विश्वास के साथ काम किया कि कंपनी एक डीलर नहीं थी। यह मानते हुए कि उन्होंने गलती की है, जुर्माना लगाने का कोई मामला नहीं बनता।

15. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ऑर्गेनो केमिकल इंडस्ट्रीज एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य:(1997) 4 एससीसी 573; भारत हेवी व्हीकल बनाम पी.एफ. आयुक्त: एआईआर 1994 एससी 1175 और कर्मचारी सरकार बीमा निगम बनाम एचएमटी लिमिटेड एआईआर 2008 एससी 1322 में प्रकाशित मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा जताया है। उक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि ऐसी स्थितियों में जहां किसी प्रतिष्ठान की ओर से अनुपस्थिति होती है जानबूझकर अपने वैधानिक दायित्वों से बचने के लिए और विशेष रूप से उन स्थितियों में, जहां देरी वास्तविक कारणों से हुई थी, प्रतिष्ठान पर हर्जाना लगाना पूरी तरह से अनुचित है। उसी के प्रकाश में, यह भी तर्क दिया गया कि

याचिकाकर्ता-कंपनी के वैधानिक बकाया के भुगतान से बचने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास की गैर-स्थापना के तथ्य के साथ-साथ छूट से उत्पन्न एक वास्तविक विश्वास के कारण हुई देरी के तथ्य पर विचार किया गया। अनुच्छेद 39 के तहत दायर किए गए आवेदन में, संबंधित अधिकारियों द्वारा जुर्माना लगाना कानून की स्थापित स्थिति की नजर में पूरी तरह से अनुचित और गलत था।

16. यहां ऊपर दिए गए मुद्दे पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों पर व्यापक रूप से विचार करने के बाद, यह पाया गया कि **मेसर्स हिंदुस्तान स्टील (सुप्रा.)** में दिया गया माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से लागू होता है। तात्कालिक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ। जबकि, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय की प्रयोज्यता वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पूरी नहीं होती है। **हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट (सुप्रा.)** और **धर्मेन्द्र टेक्सटाइल्स (सुप्रा.)** के मामले में हिस्सेदारी निम्नलिखित आधारों पर तत्काल मामले के तथ्यों से अलग है:

16/1. **हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट (सुप्रा.)** में वैधानिक दायित्वों के भुगतान में हुई देरी का आधार तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अलग था क्योंकि स्थापना अर्थात् हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन, याचिकाकर्ता-कंपनी के विपरीत एक सरकारी स्थापना नहीं थी। इसके अलावा, वर्तमान मामले के तथ्यों के विपरीत, याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा पेंशन फंड में बकाया जमा करने और उनके द्वारा दायर छूट के लिए आवेदन के तथ्य के विपरीत, हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट कंपनी ने न तो पेंशन फंड धनराशि जमा करने के अपने दायित्व को पूरा किया था और न ही उन्होंने किसी भी प्रकार की छूट के लिए आवेदन किया था, जिसके कारण अनजाने में उन्हें 1952 के अधिनियम और उसके साथ बनाए गए संबंधित नियमों के तहत आवश्यक अपने बकाए का समय पर भुगतान करने में परेशानी हो सकती थी।

16/2. **हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट (सुप्रा.)** में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए **धर्मेन्द्र टेक्सटाइल (सुप्रा.)** के मामले में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11कग के प्रावधान पर विचार करते हुए, यह माना गया कि लगाया जुर्माना उक्त प्रावधान अनिवार्य था, क्योंकि विधायिका ने "निर्धारित उत्तरदायी होगा" ('कीवर्ड' होगा) शब्दों का उपयोग किया था, जो अधिकारियों के विवेक के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है।

[2023/RJJP/001668]

इसके अलावा, धारा 11कग का प्रावधान शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से धोखाधड़ी, मिलीभगत या किसी जानबूझकर गलत बयान देने या तथ्यों को दबाने या अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान के उल्लंघन के अंतःक्रिया को समाहित करता है। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, मनःस्थिति या इरादे का प्रश्न बाधा के रूप में कार्य नहीं करेगा क्योंकि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को विधिक और वैधानिक रूप से लगाए जाने योग्य शुल्क से कम शुल्क लगाने का कोई विवेक प्रदान नहीं किया गया है। हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और 1952 के अधिनियम की धारा 14 ख के विश्लेषण पर, यह देखा गया है कि विधायिका ने "ठीक हो सकता है" ('हो सकता है' कीवर्ड हो सकता है) शब्दों का उपयोग किया है, जो पर्याप्त है क्षति के रूप में जुर्माना लगाने में अधिकारियों के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने की गुंजाइश है। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, हर्जाना लगाने के मुद्दे पर निर्णय करते समय, डिफॉल्ट पक्ष की प्रामाणिकता के अधीन, *मेन्स री* की आवश्यकता को शामिल किया जा सकता है। साथ ही, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11कग के विपरीत, 1952 के अधिनियम की धारा 14ख धोखाधड़ी, मिलीभगत या किसी जानबूझकर गलत बयान की उपस्थिति का प्रावधान नहीं करती है, जिससे जुर्माना लगाना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए, धारा 14ख दंड लगाने के लिए किसी मामले का आकलन करने में अधिकारियों द्वारा विवेक का प्रयोग करने का प्रावधान करती है। इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के नियम 32 ख के अनुसार भी, केंद्रीय बोर्ड को मामले की योग्यता के आधार पर 50% की ऊपरी सीमा तक नुकसान को कम करने का अधिकार दिया गया है; इस प्रकार, जुर्माना/क्षतिपूर्ति लगाने में संबंधित तात्पर्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विवेक की उपलब्धता है।

16/3. इस संबंध में, भारत संघ बनाम राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स ने (2009) 13 एससीसी 448 में प्रकाशित में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि **धर्मेंद्र टेक्सटाइल (सुप्रा.)** में निर्णय का मतलब यह समझा जाना चाहिए, हालांकि धारा 11कग का आवेदन स्थितियों के अस्तित्व या अन्यथा पर निर्भर करेगा। धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है, एक बार धारा किसी मामले में लागू हो जाने पर, संबंधित प्राधिकारी को राशि निर्धारित करने में कोई विवेक नहीं होगा और धारा 11 ए की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित शुल्क के बराबर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भी स्पष्ट

[2023/RJJP/001668]

किया गया था कि **धर्मद्र टेक्सटाइल (सुप्रा.)** में निर्णय केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11कग के संबंध में लागू है, न कि अन्य वैधानिक प्रावधान, जैसा कि कानून के तहत प्रदान किया गया है। यह भी ध्यान रखना उचित है कि **हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट (सुप्रा.)** के मामले में निर्णय पारित करते समय **राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स (सुप्रा.)** के निर्णय में दिए गए निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया गया था, जैसा कि अपीलार्थियोंओं के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया था। .

17. तदनुसार, मौजूदा मामले में, **हिंदुस्तान स्टील (सुप्रा.)** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि विफलता के लिए जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया था, एक वैधानिक दायित्व एक अर्ध-आपराधिक कार्यवाही का परिणाम है, और जुर्माना आमतौर पर तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि पार्टी या तो जानबूझकर कानून की अवहेलना करने के लिए बाध्य न हो या अपमानजनक या बेईमान आचरण का दोषी हो, या अपने दायित्व के प्रति सचेत उपेक्षा में कार्य न करे। आगे यह भी कहा गया कि जुर्माना केवल इसलिए नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ऐसा करना वैध है। इस संबंध में, यह विश्लेषण किया गया कि वैधानिक दायित्व को पूरा करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए या नहीं, यह न्यायिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले प्राधिकारी के विवेक और सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करने का मामला है। भले ही न्यूनतम जुर्माना निर्धारित किया गया हो, जुर्माना लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को उक्त जुर्माना लगाने से इनकार करना उचित होगा, यदि वह संतुष्ट है कि अधिनियम के प्रावधानों का तकनीकी या दोषपूर्ण उल्लंघन हुआ था या जहां उक्त उल्लंघन हुआ था यह प्रामाणिक विश्वास कि अपराधी कानून द्वारा निर्धारित तरीके से कार्य करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके अलावा, **हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट (सुप्रा.)** में निर्णय पारित करते समय एक बड़ी पीठ द्वारा पारित **हिंदुस्तान स्टील (सुप्रा.)** के उपरोक्त निर्णय पर विचार नहीं किया गया था। इसलिए, यहां ऊपर बताए गए कारणों से, उत्तरार्द्ध तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अलग है।

18. दोहराव के जोखिम पर, यह देखा गया है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, याचिकाकर्ता-कंपनी ने जानबूझकर पेंशन फंड के प्रति अपना बकाया समय पर जमा करने के अपने दायित्वों की उपेक्षा करने की कोशिश में दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्य नहीं किया,

[2023/RJJP/001668]

जैसा कि यह इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि जब 1994 के पेंशन विनियमों को अंतिम रूप देने में देरी हुई, तो याचिकाकर्ता-कंपनी ने अपनी मर्जी से वैधानिक योगदान जमा करना शुरू कर दिया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता-कंपनी को वास्तविक विश्वास था कि यदि पैराग्राफ 39 के तहत मांगी गई छूट उन्हें दी जाती है, तो उक्त राशि वापस कर दी जाएगी। इसलिए, यह निर्णायक रूप से कहा जा सकता है कि कंपनी के मामलों के प्रभारी लोगों ने बकाया राशि के भुगतान के लिए ईमानदार और वास्तविक विश्वास के साथ काम किया है कि याचिकाकर्ता-कंपनी को छूट दी जाएगी, जैसा कि मांगा गया है। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता-कंपनी की ओर से उल्लंघन कानून की जानबूझकर अवहेलना से नहीं हुआ। इसलिए, यह मानने के बावजूद कि उन्होंने गलती की है, याचिकाकर्ता-कंपनी के विरुद्ध जुर्माना लगाने का कोई मामला नहीं बनता है।

19. यह उल्लेखनीय है कि किसी कानून या धारा के सभी हिस्सों को एक साथ समझा जाना चाहिए और धारा के प्रत्येक खंड को संदर्भ और उसके अन्य खंडों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, ताकि संपूर्ण कानून का कोई सुसंगत अधिनियमन विशेष प्रावधान किया जा सके। किसी प्रावधान के शब्दों को पूरी तरह से कानून के उद्देश्य और वस्तु की कुछ कल्पना के साथ समझा जाना चाहिए। तदनुसार, धारा 14ख का प्रावधान स्पष्ट रूप से "हो सकता है" शब्द का प्रयोग करता है, जिसे जब संबंधित नियम 32 ख के साथ पढ़ा जाता है, तो 1952 के अधिनियम और उनके संबंधित नियमों के तहत अधिकारियों को जुर्माना लगाने में अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए प्रदान किए गए विवेक को और मजबूत और/या इसे कम किया जाता है।

20. इसलिए, यहां ऊपर की गई टिप्पणियों के प्रकाश में और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा की गई देरी एक वास्तविक और वास्तविक त्रुटि के कारण थी, जिसके लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रदान किया गया था, यह न्यायालय ऐसा मानता है कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण और सहायक भविष्य निधि आयुक्त द्वारा क्रमशः पारित दिनांक 19.02.2010 और 04.08.2006 के आदेशों को रद्द करना उचित है। इसके अलावा, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, 1952 के अधिनियम की धारा 14ख के तहत शुरू की गई कार्यवाही को अस्थिर माना जाता है।

21. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। सभी लंबित आवेदनों का

[2023/RJJP/001668]
निपटारा किया जाता है।

(समीर जैन), न्यायमूर्ति

JKP/90

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।